दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 17 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 257

महत्वपूर्ण एवं खास

पीएम मोदी फंटलाइन वर्कर्स को देंगे बड़ी सौगात, 18 जून को लॉन्च करेंगे कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना योद्धाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आने वाले हैं। 18 जून यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से ये ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे। देशभर के एक लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोरोना योद्धाओं को छह कस्टमाइज्ड जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। स्वास्थ्य महकमे में लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारत में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल : पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाटेक सम्मेलन के पांचवें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ओर विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि इस मंच से मैं प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप्स की दुनिया में भारत की उन्नति के बारे में अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रेड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जान-मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता रहा है। विज्ञापन और मार्केटिंग जगत की प्रमुख कंपनी पब्लिसीज ग्रुप और फ्रांस के अग्रणी मीडिया समूह लेस इकोज की ओर से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। एमओ के मुताबिक, यह आयोजन प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप इको सिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। बता दें कि विवाटेक सम्मेलन के पांचवें संस्करण का आयोजन 16 से 19 जून के बीच होना है।

देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी, 24 घंटे में 62224 नए मामले, 2542 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोराना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपाने के बाद लगातार ढ़लान पर है, लेकिन पिछले कई दिनों दैनिक मामलों में मामूली बढ़त देखी गई। यानि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,224 नए मामले दर्ज किये गये, जबकि इस दौरान 2542 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रीय मरीजों की संख्या में तेजी के साथ गिरावट आ रही है, तो कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी देखी जा रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में आए नए मरीजों के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,96,33,105 हो गई। जबकि 2542 लोगों की मौत के बाद कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,79,573 हो गई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर 1.28 फीसदी रह गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,65,432 हो गई है, जो कुल मामलों का 2.92 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 47,946 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 95.80 फीसदी हो गई है। पिछले 70 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी नौ लाख से कम हो गई है। वहीं देश में अभी तक कुल 2,83,88,100 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे।

दैनिक संक्रमण दर 3.22 फीसदी- मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 38,33,06,971 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 19,30,987 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 3.22 प्रतिशत है। पिछले नौ दिन से यह दर पांच प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं, संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 4.17 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 34वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही।

26 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण- देश में अभी तक कुल 26,19,72,014 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके हैं। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

बिना ड्राइवर ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी में रेलवे

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार विकसित करने के बीच आगामी कुछ सालों में बिना ड्राइवर के ही ट्रेन पटरी पर दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने ऐसी प्रणाली को विकसित की है जिससे ड्राइवर के ऑटो मोड पर ट्रेन चलाना आसान हो जाएगा। इसके लिए रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिल गई है।

रेलवे के सूत्रों की माने तो स्पेक्ट्रम की बदौलत ट्रेनों को अब बिना ड्राइवर चलाने की दिशा में काम हो सकेगा। स्पेक्ट्रम की वजह से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्मूथ सिगनलिंग में मदद मिलेगा। इसके अलावा ट्रेन की मूवमेंट पर भी नजर रखना आसान हो जाएगा। रेलवे को यह स्पेक्ट्रम 4जी के तहत मिला है। इसकी वजह से सिग्नल और संचार मुहैया कराना अब आसान हो जाएगा। इसके साथ ही रेलवे ने एक और अच्छी खबर दी है। उत्तर भारत में सर्दियों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। ट्रेन ड्राइवर को कोहरे के दौरान सिग्नल के लिए बाहर देखना पड़ता था। सिग्नल साफ तौर पर दिखाई ना देने के कारण ट्रेन बेहद ही धीमी गति में चलती थी। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा। स्पेक्ट्रम की वजह से ड्राइवर के कैब में ही सिग्नल मुहैया हो जाएगा जिसकी वजह से ड्राइवर को हालात के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, इस स्पेक्ट्रम के मिल जाने से ट्रेन में कई तरह की सुविधाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखा जा सकेगा। सारे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। रेलवे ट्रैक की भी निगरानी हो सकेगी। वीडियो और साउंड में भी सुधार की गुंजाइश है। ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ेगी। अभी दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून को लेकर केंद्र को लगाई फटकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा केस में यूएपीए के कड़े प्रावधानों का सामना कर रहे तीन आरोपियों को जमानत देते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उसने कहा कि हथियारों के बिना प्रदर्शन करना मूल अधिकार है, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने तीन अलग-अलग आदेशों में सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कीं। इससे पहले भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने केंद्र सरकार के लिए सख्त लहजे का इस्तेमाल कर चुके हैं। आइए जानते हैं हाल के दिनों में विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे के तीन आरोपियों देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा पर यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से निकल सकता है, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर की रेखा को धुंधला कर दिया। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

डीएपी पर प्रति बोरी मिलेगी 700 रुपये की सब्सिडी

» पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला

» डीएपी सब्सिडी पर 14775 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। वैश्विक बाजार में डीएपी उर्वरक की कीमतों में बढ़ोत्तरी की मार से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में डीएपी की प्रति बोरी पर सब्सिडी में 700 रुपये की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है। सब्सिडी के मद में सरकार 14775 करोड़ रुपये खर्च करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पिछले महीने ही डीएपी पर सब्सिडी 140 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था।

इस फैसले की जानकारी देते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में उर्वरक के रूप में किसान डीएपी पर सर्वाधिक खर्च करते हैं। सरकार का उद्येश्य है कि किसानों पर उर्वरक मामले में अतिरिक्त बोझ न बढ़े। इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद किसानों को यह पुराने दर पर ही उपलब्ध होगी।

मंडाविया ने कहा कि डीएपी की 50 किलो की बोरी पहले भी किसानों को 1200 रुपये में मिलती थी। अब भविष्य में भी किसानों को डीएपी के लिए इतना ही भुगतान करना होगा। इसके लिए सरकार ने डीएपी की एक बोरी पर सब्सिडी को 500 रुपये से बढ़ा कर 1200 रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में डीएपी की कीमत प्रति बोरी 2400 रुपये हो गई है।

उन्होंने कहा कि किसानों की कृषि लागत घटाने और उनके सामने अपनी उपज को बेचने के अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस समय सरकार यूरिया पर 900 रुपये प्रति बोरी की दर से सब्सिडी दे रही है।

समुद्री संसाधनों की खोज के लिए होगा समुद्र मंथन

» केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को मंजूरी प्रदान की

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'गहरे समुद्र मिशन' को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की हुई आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि गहरे समुद्र के तले एक अलग ही दुनिया है। पृथ्वी का 70 प्रतिशत हिस्सा समुद्र है । उसके बारे में अभी बहुत अध्ययन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सीसीईए ने 'गहरे समुद्र संबंधी मिशन' को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे एक तरफ ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। जावड़ेकर ने बताया कि समुद्र में 6000 मीटर नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ है। इस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के जलस्तर के बढ़ने सहित गहरे समुद्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन किया जायेगा। मंत्री ने बताया कि गहरे समुद्र संबंधी मिशन के तहत जैव विविधता के बारे में भी अध्ययन किा जायेगा।

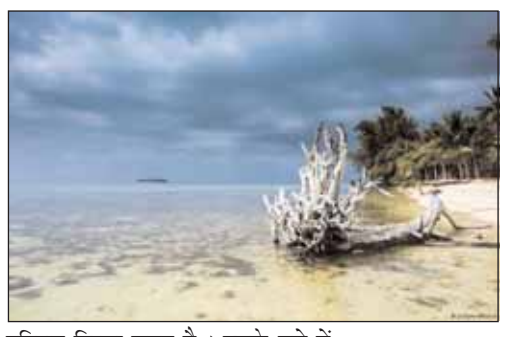

उन्होंने बताया कि इसके तहत समुद्रीय जीव विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाने के लिये उन्नत समुद्री स्टेशन (एडवांस मरीन स्टेशन) की स्थापना की जायेगी । इसके अलावा थर्मल एनर्जी का अध्ययन किया जायेगा। जावड़ेकर ने बताया कि इस बारे में अभी दुनिया के पांच देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन के पास ही प्रौद्योगिकी । ऐसी प्रौद्योगिकी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है । ऐसे में इस मिशन से खुद प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए डीएपी पर सबसिडी भी 700 रुपये प्रति बोरी बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने बताया कि केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) उर्वरक पर प्रति बैग 700 रुपये सबसिडी बढ़ा दी है। इससे सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ रुपये का बोझ आएगा।

ब्लैक फंगस की दवाओं में किसी राज्य से नहीं किया भेदभाव : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) के इलाज के लिए फंगस रोधी दवाएं राज्यों को जरूरत के आधार पर आवंटित की गई हैं। केंद्र ने कहा कि इन दवाओं के आवंटन में सहित किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं किया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि केंद्र नियमित रूप से महाराष्ट्र को फंगस रोधी दवाओं की आपूर्ति कर रहा है।

उन्होंने बताया कि म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंफोटेरिसिन बी की आपूर्ति कम है, लेकिन केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों द्वारा की जा रही मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सिंह ने कहा, देश में दवा की उपलब्धता और राज्यों की मांग के अनुरूप हम आवंटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम (भारत सरकार) दवा की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कार्यबल का गठन किया गया है, उच्चतम न्यायालय भी निगरानी कर रहा है। अमेरिका की कंपनी से एंफोटेरिसिन बी के नवीनतम एवं प्रभावी दवा के आयात के लिए हमने छह दवा कंपनियों को लाइसेंस दिया है।

लॉकडाउन के बाद खुलने के पहले दिन ही कुतुब मीनार, लाल किला पहुंचे पर्यटक

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक भवन, स्मारक स्थल और संग्रहालय आज से पर्यटको के लिए खोल दिये गए हैं। खुलने के पहले दिन ही पर्यटक उत्साहपूर्वक कुतुब मीनार और लाल किले का दीदार करने पहुंच रहे हैं।

कोरोना महामारी के कारण एएसआई ने 15 जून तक इन्हें बंद करने का निर्णय लिया था। हालांकि इन स्मारकों में पहले दिन ज्यादा पर्यटक नजर नहीं आए। हालांकि, पर्यटकों में स्मारकों के खुलने की खुशी देखी जा सकती थी।

कुतुब मीनार और लालकिला परिसर को पर्यटकों के आने से पहले सैनिटाइज किया गया था, इतना ही नहीं पहले की तरह लोग किला परिसर पहुंचकर भारतीय संग्रहालय और पेटीएम के सहयोग से लगाए गए क्यूआर कोड से भी ई-टीकट बुक कर सकेंगे। पर्यटकों को परिसर में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

साथ ही परिसर में दाखिल होने से पहले पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तापमान सामान्य होने पर ही परिसर में जाने दिया जाएगा। लालकिले में कार्यरत अधिकारियों ने आरएनएस को बताया कि, सुबह से ही पर्यटकों का आना जारी है, फिलहाल करीब 50 पर्यटक ही लाल किला का दीदार करने आये हैं। पर्यटकों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। अभी तक जितने भी पर्यटक आये है वह सभी यहीं के निवासी है, कोई विदेशी पर्यटक हमें नजर नहीं आया है।

सुबह से लोग अपने परिवार और परिजनों के साथ लाल किला और कुतुब मीनार देखने पहुंचे। दिल्ली निवासी शहजाद ने बताया, लंबे वक्त से लाल किला बंद था, वहीं कोरोना महामारी के कारण घरों में ही हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब मामले कम हो रहे हैं तो ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। लाल किला और अन्य स्मारक घूमने से इंसान को मानसिक रूप से भी आराम मिलेगा। कुतुब मीनार का दीदार करने पहुंचे अर्चित ने बताया, हम लोग बहुत लंबे वक्त से कुतुब मीनार खुलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण ऑनलाइन टिकट के करने में थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन कुछ देर बाद हमारी टिकट बुक हो गई। फिलहाल घूम रहे हैं ।

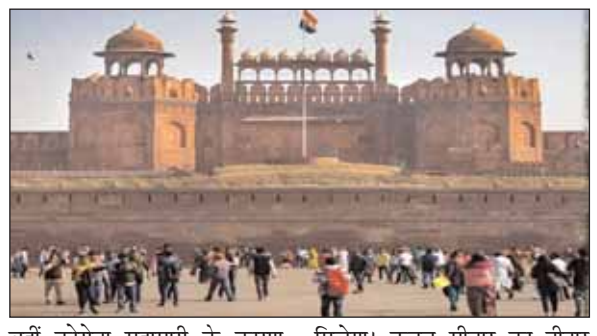

यदि समय बचता है तो अन्य स्मारकों का भी दीदार करने जाएंगे। सोमवार को ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा था, मंत्रालय ने एएसआई के सभी स्मारकों को 16 जून 2021 से विधिवत खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएँ । हालांकि एसएआई ने पहले 16 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के लिए सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद एसएसआई ने 12 मई को एक बार फिर इन्हे 15 जून तक बंद रखने के लिए आदेश जारी कर दिया था।

दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, अब्दुल रहीम खान-एखाना का मकबरा व दूसरे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को लोगों के दीदार के लिए बुधवार से खोल दिया गया है। एएसआई के देशभर में 3693 संमारक और 50 संग्रहालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि, परिस्थितियों के मुताबिक इन्हें खोलने का अंतिम निर्णय जिला प्रशासन के पास होगा।